(b) Does not arise.

(c) Need for fixing minimum educational qualification and retirement age of politicians, has not been felt by the Government.

Reservation for women in Lok Sabha and Assemblies

2770. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to provide reservation for women in Lok Sabha and Assemblies, and

(b) if so, the details thereof;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मतदाता-सूची

2767. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लोक सभा और विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता-सूची को अद्यतन बनाने के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मतदाताओं को पहचान-पत्र देने के बारे में भी कोई निर्णय ले रही है; और

(घ) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने के मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। तथापि, मतदाताओं की अत्यधिक संख्या, व्यय और इसको चलाने में प्रशासनिक उपाय को ध्यान में रखते हुए, देश भर में बहुउद्देश्यीय फोटो-पहचान पत्रों को लागू करने में उनकी प्रक्रिया प्रारंभ कर देने के पश्चात् पांच वर्ष से कम समय लगने की संभावना नहीं है।

Ceiling on the fees of lawyers

2772. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to put ceiling on the legal fees of lawyers of various High Courts and Supreme Court; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM): (a) and (b) Government is not considering any specific proposal for putting a ceiling on the legal fees of lawyers. However, the Committee on Petitions (Ninth Lok Sabha) in its Second Report recommended that the possibility of setting up of an administrative machinery which may be able to regulate the fees charged by lawyers from their clients, may be explored by the Government. Views of Agencies concerned in this regard are awaited.

विधिक सहायता योजना के अधीन आवंटित की गई धनराशि

2773. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को विधिक सहायता योजना की अधीन कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस योजना के अधीन कितने व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराई गई तथा राज्य में उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह योजना पूर्णत: असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): उत्तर प्रदेश सरकार और विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान